साप्ताहिक
Live not just breaTHE

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

दि कार्मिक पोस्ट

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 9, अंक : 25 (प्रति बुधवार),इन्दौर, 7 फरवरी 2024 से 13 फरवरी 2024 पेज :8 कीमत : 3 रुपये

विवादास्पद घोटाले को लेकर श्रीलंका के पर्यावरण मंत्री ने दिया इस्तीफा

कोलंबो श्रीलंका के पर्यावरण मंत्री केहेलिया रामबुकवेला ने को इस्तीफा दे दिया। रामबुकवेला को स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान विवादास्पद मानव इम्युनोग्लोबुलिन खरीद घोटाले को लेकर कुछ ही दिन पहले गिरफ्तारी किया गया था। पुलिस के अपराध जांच विभाग द्वारा 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद 2 जनवरी को रामबुकवेला को गिरफ्तार किया गया था। रामबुकवेला ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा पत्र भेजा था। राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि इस्तीफा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और इसे सरकारी गजट के माध्यम से प्रकाशन के लिए निर्देशित किया गया है। उसने कहा कि हिरासत में लिये जाने के बाद मंत्री को बीमार होने के कारण जेल अस्पताल में ले जाया गया था।

देश की वायु गुणवत्ता में आया सुधार, महज आठ शहरों में दमघोंटू रह गई है हवा

नई दिल्ली। इस साल में यह पहला मौका है जब देश की वायु गुणवत्ता में इतना सुधार देखा गया है। आंकड़ों की मानें तो देश के 246 शहरों में से महज सात शहरों में वायु गुणवत्ता खराब% है। इन शहरों में अगरतला (226), बारीपदा (234), बक्सर (251), कटक (223), हाजीपुर (208), हनुमानगढ़ (208) और श्रीगंगानगर (210) शामिल हैं। वहीं देश में केवल अंगुल में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार है। मतलब कि देश में अंगुल अकेला ऐसा शहर है, जहां वायु गुणवत्ता %बेहद खराब दर्ज की गई है।

इसी तरह यदि दिल्ली की बात करें तो देश की राजधानी में कल के मुकाबले प्रदूषण के स्तर में गिरावट जरूर देखी गई है। हालांकि इसके बावजूद अभी भी वायु गुणवत्ता मध्यम स्तर पर बनी हुई है। वहीं इसके विपरीत देश के सबसे साफ शहर की बात करें तो इस मामले में मैहर सबसे ऊपर है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 25 दर्ज किया गया है। इसी तरह 15 अन्य शहरों में भी वायु गुणवत्ता बेहतर बनी हुई है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 50 या उससे कम दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 08 फरवरी 2024 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, देश के 246 में से 16 शहरों में हवा %बेहतर% (0-50 के बीच) रही। वहीं 107 शहरों में वायु गुणवत्ता %संतोषजनक% (51-100 के बीच) थी, जबकि 115 शहरों में वायु गुणवत्ता %मध्यम% (101-200 के बीच) रही।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने हमीदिया अस्पताल पहुंचकर हरदा हादसे में घायल नागरिकों का हाल-चाल पूछा

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज शाम हमीदिया अस्पताल में इमरजेंसी विभाग और आईसीयू पहुंचकर हरदा विस्फोट हादसे में घायल हुए नागरिकों से भेंट कर उनका हाल-चाल पूछा । मुख्यमंत्री डॉ यादव ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और चिकित्सा विशेषज्ञों से किए जा रहे इलाज की जानकारी प्राप्त कर घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने चिकित्सकों से कहा कि घायलों के बेहतर उपचार में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने घायलों को आश्वस्त किया कि उनका अच्छे से अच्छा इलाज होगा। घायलों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने हरदा हादसे में घायल श्री जितेंद्र ,श्री महबूब शाह, श्री महेंद्र कुशवाहा, श्री दिनेश सोनी ,श्री राम सजीवन, श्रीमती अमीना, श्री बाबूलाल और श्री शोभाराम से भेंट कर उनके स्वास्थ्य और उपचार का हालचाल लिया। मुख्यमंत्री डॉ यादव के हमीदिया अस्पताल पहुंचने पर हरदा हादसे में घायल हुए लोगों का उपचार कर रहे चिकित्सकों ने बताया कि सभी घायलों को आवश्यक उपचार दिया जा रहा है। ये सब शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल उपस्थित थे।

संकट की घड़ी में सरकार प्रभावितों के साथ, पूरी मदद दी जाएगी - मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव

जिला अस्पताल में घायलों का हाल-चाल जाना, गंभीर घायलों को एक-एक लाख रु. की मदद

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जिला अस्पताल हरदा पहुंचकर पटाखा दुर्घटना में हुए घायल व्यक्तियों से मुलाकात कर उनका हाल-चाल जाना। डॉ. यादव ने अस्पताल प्रबंधन को दुर्घटना में घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। उन्होंने घायलों को आश्वस्त किया कि संकट की घड़ी में सरकार प्रभावितों के साथ है। पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाएगी।

घायल व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को बताया कि हादसे में उनके घर पूरी तरह टूट गए हैं। मवेशी भी मारे गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हरदा कलेक्टर को क्षतिग्रस्त आवासों की लिस्टिंग कर पीड़ित परिवारों को आवास के लिये उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घायल मवेशियों का बेहतर उपचार किया जाएगा। मृत हुए मवेशियों का मुआवजा भी प्रभावित व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

पूर्व मंत्री श्री कमल पटेल, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय दुबे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री जयदीप प्रसाद, संभागायुक्त नर्मदापुरम डॉ पवन कुमार शर्मा, आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग श्री सुदाम पी खाड़े, पुलिस महानिरीक्षक श्री इरशाद वली, हरदा कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

गंभीर घायलों को 1-1 लाख रु. की दी मदद

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हादसे में गंभीर रूप से घायल 5 व्यक्तियों को गोविंद मूलचंद चंदेल, हेमंत दिनेश, असगर सज्जाद हुसैन, यूसुफ अख्तर और घनश्याम नर्मदा प्रसाद को 1-1 लाख रुपए राशि की आर्थिक सहायता का चेक वितरित किया। उन्होंने अन्य घायलों को 25-25 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी।

मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रूपये की मदद दी गई

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने मृतकों के परिजनों को ढांढस बधाया। उन्होने मृतकों के परिजनों को आश्वस्त करते हुए कहा कि इसके अतिरिक्त भी हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को हुई इस दुर्घटना में जिन 10 लोगों की मृत्यु हुई थी, उनमें बानो बी पिता सलीम खान, प्रियांशु पिता मुन्नालाल प्रजापति, मुबीन खान पिता सफुर खान, अनुज पिता शोभाराम कुचबंदिया, आबिद पिता रहमान खान, उषा पिता मुकेश चंदेल, मुकेश पिता तुलसीराम बेलदार, अयाज पिता सिराज खान, प्रमिलाबाई पिता सुनील चैहान तथा रहीम पिता रौशन खान शामिल है।

एरोसोल और नदियों में बहने वाले प्रदूषकों की वजह से बदल रहा है समुद्रों में फास्फोरस चक्र

नई दिल्ली। समुद्री फास्फोरस चक्र को लेकर किया गया नया अध्ययन समुद्रों के पारिस्थितिक तंत्र पर मानवजनित गतिविधियों के बुरे प्रभाव को उजागर कर रहा है। यह अध्ययन ईस्ट एंग्लिया विश्वविद्यालय और चीन के महासागर विश्वविद्यालय की साझेदारी में किया गया है। अध्ययन में तटीय जल में माइक्रोएल्गे या फाइटोप्लांकटन पर एरोसोल और नदियों में प्रदूषकों के बहाव के प्रभाव को देखा गया है।

यहां बताते चलें कि माइक्रोएल्गे या फाइटोप्लांकटन सूक्ष्म शैवाल हैं जो नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित अध्ययन में मानवजनित नाइट्रोजन पंप की पहचान की गई, जो फास्फोरस चक्र को बदलता है, इसकी वजह से तटीय जैव विविधता और संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में भी बदलाव आ रहा है।

एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में, माइक्रोएल्गे, जिसे फाइटोप्लांकटन भी कहा जाता है, मछली, झींगा और जेलीफिश सहित समुद्री जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए भोजन प्रदान करते हैं।

प्रमुख शोधकर्ता हाओयू जिन ने कहा, हमारा काम मानव निर्मित यूट्रोफिकेशन के परिणामों को जानने के लिए आधार प्रदान करता है, जिससे पोषक तत्व बड़े पैमाने पर शैवाल खिलाते हैं और नाइट्रोजन-फॉस्फोरस पोषक संरचना को गड़बड़ी पैदा करते हैं। विशेष रूप से आर्थिक गतिविधि के कारण तटीय क्षेत्र, जो दुनिया भर में सबसे अधिक उत्पादक हैं, वहां कचरे का उत्पादन बढ़ रहा है जिसमें तरल पदार्थ और एरोसोल शामिल हैं। जो सबसे अधिक नदियों में और उसके बाद वायुमंडल में फैला है। अध्ययन से पता चलता है कि नदियों और वायुमंडल में बढ़ते इन अपशिष्ट उत्पादों में घुलनशील नाइट्रोजन प्रमुख पोषक तत्व है। हालांकि, जीवन के लिए अन्य पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है और जो समान रूप से महत्वपूर्ण है वह फॉस्फोरस है। अध्ययनकर्ता ने बताया, हमने जो पाया उसमें नाइट्रेट की मात्रा भी शामिल है। नदियों और वायुमंडल में अपशिष्ट उत्पाद तटीय महासागरों में फास्फेट को इतना कम कर देते हैं कि शैवाल अंततः इस पोषक तत्व द्वारा सीमित हो जाते हैं। हालांकि, उनमें से कुछ फास्फोरस के एक ढेर तक पहुंचने में सक्षम हैं जो अतीत में तटीय महासागरों में कम भूमिका निभाते थे जिन्हें विघटित कार्बनिक फास्फोरस (डीओपी) के रूप में जाना जाता है। शोधकर्ताओं ने चीन के तटीय समुद्र में कई छोटे प्रयोग किए। फाइटोप्लांकटन को विकास के लिए आमतौर पर विघटित अकार्बनिक फास्फोरस (डीआईपी) की आवश्यकता होती है, लेकिन चूंकि यह नाइट्रोजन के स्तर में वृद्धि से सीमित है, सूक्ष्म शैवाल विघटित कार्बनिक फास्फोरस (डीओपी) का उपयोग करने के लिए क्षारीय फॉस्फेट की गतिविधि को बढ़ाने में सक्षम हैं।

बाग में डायनासोर जीवाश्म पार्क के लिए 89 हेक्टेयर जमीन संरक्षित

धार (संवाददाता द्वारा) धार जिले का अपना ऐतिहासिक और वैभवकालीन इतिहास रहा है। रियासतकालीन ऐतिहासिक इमारतें मांडू व अन्य जगह विद्यमान हैं। वहीं बाग के समीप डायनासोर जीवाश्य मिले हैं। नर्मदा घाटी के तहत आने वाले क्षेत्र में दुनिया के सबसे विशालकाय जानवर डायनासोर होने के प्रमाण मिल चुके हैं। इसी के चलते बाग के समीप डायनासोर जीवाश्म पार्क बनाने की कार्ययोजना तैयार हुई। इसके लिए वन विभाग ने बाग और पाड्ल्या गांव के बीच 89 हेक्टेयर जमीन संरक्षित की है।

यहां डायनासोर के जीवाश्म, अंडे और वर्षों पुराने पेड़ों के अवशेष हैं। इनके संरक्षण के लिए विभाग की ओर से यहां पार्क तैयार किया जाएगा। फिलहाल संरक्षित स्थल पर तार फेसिंग सहित अन्य कार्य किए जा रहे हैं। पहुंच मार्ग बनाया जा रहा है। ताकि पर्यटकों को आने में कोई परेशानी न हो। वन विभाग के एसडीओ संतोष रनसोरे ने बताया कि विभाग के माध्यम से छोटे-मोटे काम लगातार चल रहे हैं। पर्यटन को आकर्षित करने के लिए शासन स्तर पर लाइट एंड साउंड शो शुरू करने की योजना है। डायनासोर पार्क को विकसित करने के लिए पर्यटन, पुरातत्व और संस्कृति विभाग मिलकर काम करेंगे। पिछले महीने कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने विभागों की बैठक लेकर निर्देश दिए थे। इसमें तय हुआ था कि बाग में बनने वाले जीवाश्म पार्क में पर्यटकों की सुविधा के लिए लाइड एंड साउंड शो शुरु किया जाएगा। हालांकि अभी इसके लिए बजट का आवंटन नहीं मिला है। अधिकारियों का कहना है कि बजट मिलने के बाद ही कार्ययोजना के अनुसार काम होंगे। बाग एवं मांडव के आसपास के स्थानों में करोड़ों वर्ष पूर्व के जीवाश्म बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं।

मैथ्स गार्डन से बच्चे सीख रहे गणित और पर्यावरण संरक्षण

कोरबा । गणित जैसे कठिन विषय को बच्चों में सरलता से समझाने के लिए स्याहीमुड़ी के शिक्षकों ने स्कूल के उद्यान को मैथ्स गार्डन का स्वरूप दिया है। प्रकृति के साथ बच्चे आसानी से गणित सीख सकें इसके लिए क्यारियों को त्रिकोण, आयात व गोलाई की आकृति प्रदान की गई है। रोपे गए पौधों में गणित के सूत्र को लटकाया गया हैं। इससे बच्चे क्यारी का क्षेत्रफल, पौधों की मोटाई आदि माप सकते हैं। गणित के साथ बच्चे पर्यावरण संरक्षण के भी गुर सीख रहे हैं।

जिला उद्यानिकी विभाग की ओर से स्कूल के बच्चों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने के लिए उद्यानिकी के योजनाओं से अवगत कराया जा रहा है। प्रारंभिक तौर पर इस योजना के अंतर्गत आत्मानंद स्कूल सिंघिया, हाई स्कूल पताढ़ी, स्याहीमुड़ी, पोड़ी लाफा को चयन किया गया हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत चलाए जा रहे इस योजना का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति बच्चों को सजग करना, कृषक श्रेणी में आने वाले विद्यार्थियों के स्वजन को योजनाओं की जानकारी देना व फलदार पौधों का रकबा बढ़ाना है। सरकार के इस योजना पर नवाचार करते हुए हाई स्कूल स्याहीमुड़ी के शिक्षकों ने स्कूल के उद्यान को मैथ्स गार्डन का स्वरूप दिया है। विद्यालय प्राचार्य फरहाना अली ने बताया कि गणित जैसे विषय से बच्चे अक्सर दूर भागते हैं। बच्चों के लिए यह रूचिकर बने इसके लिए हमने उद्यान में गणित सिखाने का नवाचार किया है। बच्चों को गणित का प्रायोगिक ज्ञान सीखने को मिल रहा है। क्यारियों को अलग-अलग स्वरूप दिया है। जिसकी लंबाई चौड़ाई के आधार पर बच्चे आसानी से उसका क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं। क्यारियों के बीच सड़क की चौड़ाई व दूरी मापने की विधि आसानी से सीख रहे हैं। गणित के विभिन्न आयामों से संबंधित सूत्र को हमने पौधों में लगाया है। रोज उसे देखकर सीखने में बच्चों को आसानी हो रही है। स्कूल में इकोक्लब का गठन किया गया है। जिसका उद्देश्य खेल खेल में पाठ्यक्रम से जुड़े शिक्षा का आसान बनाना है। अली का यह भी कहना है प्रायोगिक तौर पर शुरूआत की गई इस पहल का बेहतर परिणाम देखने को मिल रहा। गणित जैसे विषय में जिन बच्चों रूचि नहीं थी अब वे आसानी से इस नवाचार के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। प्राचार्य अली कहना है कि जिले में पहली बार यह नवाचार की गई है। हमारा प्रयास रहेगा कि इस माध्यम को अन्य स्कूलों में भी शुरू किया जाए ताकि बच्चे आसानी से सीख सकें। प्राचार्य अली ने बताया कि स्कूलों में संसाधन की कोई कमी नहीं। प्रत्येक स्कूलों में उद्यानिकी को विकसित किया जा सकता है। शासन की ओर से प्रतिवर्ष स्कूलों को समग्र शिक्षा के लिए 5,000 राशि प्रदान की जाती है। इस राशि का उपयोग स्कूल के उद्यान के विकास के लिए किया जा रहा है। प्राचार्य बताया कि उद्यान में बच्चे अब तक केवल पर्यावरण संरक्षण की पाठ सीख रहे थे। अब गणित का पाठ शामिल किए गए जाने से वे इसे आसानी से समझ रहे हैं। जिला उद्यानिकी से बच्चों को उद्यानिक विभाग की ओर से बच्चों को विविध जानकारी भी दी गई है। दो अलग-अलग प्रकृति के फलों एक पेड़ में तैयार करने की कलम विधि सिखाई जा रही है। इस योजना के माध्यम से बच्चे यह भी सीख रहे हैं, कौन से मौसम में किस तरह के पौधे रोपे जाते हैं। सब्जी, फल आदि कितने दिन में तैयार होते हैं। साथ ही उन्हे इस बात की भी जानकारी दी जा रही है कि पौधों में बीमारी आने पर किस तरह से उपचार किया जाता है। जिला उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक आभा पाठक ने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत स्कूलों में विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रशिक्षित किया जाना है। प्रारंभ में पांच विकासखंड के एक-एक स्कूल का चयन किया गया हैं। आगामी वर्षों अधिक से अधिक स्कूलों चयन किया जाएगा। विद्यार्थियों के अलावा शिक्षकों को भी जानकारी देने के साथ स्कूल में रोपणी के लिए फलदार पौधे प्रदान किया जाएगा।

क्या भारत ने आय की गरीबी को मापना बंद कर दिया है?

पहली बार किसी भारतीय वित्त मंत्री के बजट भाषण में बहुआयामी गरीबी शब्द का जिक्र किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने 'मदद' देकर 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है। बहुआयामी गरीबी, गरीबी और अभाव को देखने-समझने का एक बेहतर जरिया है। आय की गरीबी से आमतौर पर गरीबी का निर्धारण या गरीब की पहचान होती है लेकिन गरीबी तो बहुआयामी होती है। इसलिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक के तीन महत्वपूर्ण आयाम हैं। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन स्तर शामिल है।

नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक तैयार किया है जिससे तीनों आयामों को परखा जा सकता है। प्रत्येक आयाम को मापने के लिए आयोग के पास संकेतक हैं जो सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) से संबद्ध हैं । स्वास्थ्य के संकेतक हैं- पोषण, बाल व किशोर मृत्युदर और मातृ स्वास्थ्य। शिक्षा के संकेतकों में स्कूल जाने के वर्षों और उपस्थिति को शामिल किया गया है। जीवन स्तर के संकेतकों में स्वच्छ ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्तियां व बैंक खाते शामिल हैं।

इनके आधार पर नीति आयोग ने देश में बहुआयामी गरीबी का मापा है और कहा है कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इसे वित्त मंत्री ने 'गरीबी' में कमी का दावा करने के लिए उद्धृत किया है। नीति आयोग की गणना के अनुसार, 2005-06 में बहुआयामी गरीबी 55.3 प्रतिशत थी जो 2013-2014 में 29.2 प्रतिशत हो गई थी। अगले 10 वर्षों यानी 2022-2023 में यह 11.3 प्रतिशत तक घट गई। लेकिन, इस सूचकांक में आय की गरीबी यानी वह पहलू शामिल नहीं है जो भारत में गरीबी मापने में उपयोग होता आया है। 'गरीब' केंद्रित हमारी सभी विकास परियोजनाएं गरीबी रेखा पर आधारित हैं जो गरीबी सर्वेक्षण से तय होती है (भारत आय के स्तर का निर्धारण करने के लिए व्यय के आंकड़ों का उपयोग करता है)। भारत ने 2011-2012 के बाद से गरीबी का एक भी सर्वेक्षण नहीं किया है। 2014 के बाद से उपभोग व्यय का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। इसलिए, आय की गरीबी का कोई आंकड़ा ही नहीं है जो गरीबी रेखा को मापने का आधार है और जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल है।

भारत को 2022 तक गरीबी का उन्मूलन करना था यानी 2030 के एसडीजी से 8 साल पहले इसे प्राप्त करना था। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 सितंबर 2017 को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की एक बैठक में यह वादा किया था। उन्होंने जिस नए भारत का वादा किया था, यह उसके केंद्र में था। वर्तमान सरकार जिस बहुआयामी गरीबी में अप्रत्याशित गिरावट का दावा करती है, उसके पास गरीबी की वास्तविक स्थिति पर पर्दा डालने के लिए भी बहुत कुछ है। छिपाने की यह मंशा तब और स्पष्ट हो जाती है जब बहुआयामी गरीबी का आंकड़ा गरीबी का पर्याय बन जाता है और ज्यादातर सरकारी दस्तावेजों में गरीबी में कमी दर्शाने के लिए इसी आंकड़े का हवाला दिया जाता है। ऐसा लगता है कि आगे भी गरीबी उन्मूलन को नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार पर मापा जाएगा जिसमें आय की गरीबी शामिल नहीं है। पहले ही दावे किए जा रहे हैं कि विभिन्न सरकारी कल्याण कार्यक्रमों ने लोगों की 'आय' में वृद्धि की है। उदाहरण के लिए, जन वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले मुफ्त अनाज को पारिवारिक आय की वृद्धि के तौर पर पेश किया जा रहा है। 30 जनवरी 2024 को नीति आयोग ने अपनी वेबसाइट पर भारतीय मॉडल ऑफ इन्क्लूसिव ग्रोथ- सबका साथ सबका विकास नामक वर्किंग पेपर प्रकाशित किया। नीति आयोग के सदस्य और पेपर के लेखक अरविंद विरमानी इसमें लिखते हैं कि इस पेपर ने आधिकारिक रूप से विकास, समृद्धि और गरीबी के नए मापक को स्थापित किया है जिसे 'भारतीय' कहा गया है। इसमें लिखा है कि सामाजिक कल्याण का भारतीय दृष्टिकोण बहुमुखी है। इसमें प्रत्यक्ष हस्तांतरण और सेवाओं के रूप में अप्रत्यक्ष सब्सिडी, नगद हस्तांतरण (जैसे किसानों को) और मुफ्त या बाजार भाव से कम पर वस्तुओं व सेवाओं (जैसे छात्रवृत्ति) का प्रावधान और मूलभूत आवश्यकताओं की विस्तृत श्रृंखला शामिल है। पेपर ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक को गरीबी मापने के 'भारतीय' तरीके के रूप में भी मुहर लगाई है। इसमें कहा गया है, विकास अर्थशास्त्रियों ने इन भारतीय कल्याण और विकास प्रथाओं में से कुछ को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की है जिन्हें बहुआयामी गरीबी संकेतक कहा जाता है।

उमरीखेड़ा इंदौर में विकसित होगा ईको टूरिज्म एवं एडवेंचर पार्क

पर्यटक ले सकेंगे प्राकृतिक सौंदर्य एवं नाइट सफारी का आनंद

जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने वन मंत्री श्री चौहान को दिया प्रस्ताव

इंदौर जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान को उमरीखेड़ा, इंदौर में ईको टूरिज्म एवं एडवेंचर पार्क बनाए जाने और रालामंडल अभ्यारण में आवश्यक विकास कार्य कराए जाने संबंधी प्रस्ताव सौंपा है। वन मंत्री श्री नागर सिंह चौहान ने जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट से भोपाल में उनके निवास पर मुलाकात की और आश्वस्त किया कि यह कार्य शीघ्र कराया जाएगा।

प्रस्ताव अनुसार इन क्षेत्रों को विकसित किए जाने से इंदौर जिले के साथ-साथ उज्जैन, देवास, खंडवा, धार, शाजापुर, सीहोर, भोपाल आदि जिलों के सैलानियों के लिए ये स्थान भ्रमण के लिए नेशनल पार्क के विकल्प के रूप में मिल सकेंगे और यहां पहुंचकर वे प्राकृतिक सौंदर्य, वन्य जीव एवं नाइट सफारी का आनंद लेकर रोमांचित हो सकेंगे। उमरीखेड़ा ऐसा पर्यटन स्थल है जहां प्रतिदिन सैलानी पहुँचकर वन्यजीव प्रेमी प्राकृतिक सौंदर्य एवं रोमांच का अनुभव करते हैं। ईको टूरिज्म एवं एडवेंचर पार्क उमरी खेड़ा में 290 हेक्टेयर क्षेत्र में बटरफ्लाई पार्क, ट्रैकिंग एडवेंचर जोन और इंटरप्रिटेशन सेंटर आदि हैं। विभाग द्वारा ईको टूरिज्म एवं एडवेंचर पार्क उमरीखेड़ा को विकसित करने के लिए लगभग 7 करोड रुपए की लागत का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत सैलानियों के लिए 145 लाख रूपये की लागत से 15 कॉटेज, 15 स्विस टेंट और 20 अन्य टेंट तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही 85 लाख रूपये की लागत से एडवेंचर पार्क, चिल्ड्रन पार्क, वॉच टॉवर्स, बटरफ्लाई पार्क, हर्ब्स पार्क, ओपन एयर थिएटर आदि का विकास किया जाएगा। योजना में 105 लाख रुपए की लागत से ट्रैकिंग ट्रेल, साइकलिंग ट्रेल, लोटस पाउंड और लैंडस्कैपिंग वर्क किया जाएगा। योजना में 90 लाख रूपये की लागत से कैफे एंड रेस्टोरेंट विकसित किया जाएगा। योजना में 80 लाख रुपए की लागत से सोलर पावर सिस्टम लगाया जाएगा। इसके साथ ही 195 लाख रुपए की लागत से साइड इंफ्रूवमेंट, ब्यूटीफिकेशन कार्य एवं अन्य कार्य कराए जाएंगे। रालामंडल अभयारण्य लगभग 275 हेक्टेयर क्षेत्र फैला हुआ है। इसको विकसित करने के लिए विभाग द्वारा 3 करोड़ 94 लाख रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

प्रदेश में 275 सीएम राइज स्कूल संचालित

आगामी 10 वर्षों में 9,200 सीएम राइज स्कूल शुरू करने का कार्यक्रम

इंदौर (नगर प्रतिनिधि) प्रदेश में सरकारी स्कूलों में सर्व-सुविधायुक्त वातावरण के साथ विद्यार्थियों को रोचक एवं आनंददायक शिक्षा देने के लिये सीएम राइज स्कूल की स्थापना की गई है। पहले चरण में 275 सीएम राइज स्कूल प्रारंभ किये जा चुके हैं। आने वाले 10 वर्षों में प्रदेश में 9,200 सीएम राइज स्कूल शुरू करने का कार्यक्रम तय किया गया है।

सीएम राइज स्कूल में के.जी. से कक्षा 12वीं तक के संचालन की व्यवस्था के साथ अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था की गई है। राज्य में 269 सीएम राइज स्कूलों के नवीन भवन निर्माण के लिये स्कूल शिक्षा विभाग ने 9 हजार 500 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी भी दी है। इन स्कूलों में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिये डिजिटल कक्षा, पूर्ण रूप से सुसज्जित प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय, कला, नृत्य, संगीत एवं योग शिक्षण की व्यवस्था भी की गई है।

स्कूलों में परिवहन की व्यवस्था- सीएम राइज स्कूलों में दूर से आने वाले विद्यार्थियों को सुविधा देने के मकसद से परिवहन की व्यवस्था भी की जा रही है। इससे स्कूल के आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। सीएम राइज स्कूल में बेहतर नेतृत्व प्रदान करने की दृष्टि से इन स्कूलों के प्राचार्यों को भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर में प्रशिक्षण दिलाया गया है। इसके साथ ही प्राचार्यों को राष्ट्रीय स्तर के ख्याति-प्राप्त विद्यालयों में एक्सपोजर विजिट कराया गया है।

योजना का द्वितीय चरण- सीएम राइज योजना के दूसरे चरण में 5,986 स्कूलों का चयन किया गया है। इनमें से 258 स्कूलों को दूसरे चरण में संचालित करने की स्कूल शिक्षा विभाग ने स्वीकृति जारी की है।

प्राचार्य हेण्ड-बुक प्रदेश में सीएम राइज स्कूलों में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को विश्व-मानकों के अनुरूप पूरा करने की दृष्टि से प्राचार्य और शिक्षकों के लिये अलग-अलग हेण्ड-बुक तैयार की गई हैं। विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति के लिये सीएम राइज स्कूलों के लिये छात्र डायरी तैयार की गई है। छात्रों के चिंतन एवं प्रभावी शिक्षण के लिये आवश्यक टूल्स को डायरी के पृष्ठों में शामिल किया गया है। इसके जरिये छात्रों की रचनात्मक गतिविधियों एवं शैक्षणिक प्रगति से पालकों को निरंतर अवगत कराया जाता रहेगा।

विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में संस्कृत की होगी महत्वपूर्ण भूमिका- उच्च शिक्षा मंत्री श्री परमार

विश्वगुरु भारत के पुननिर्माण में बनना होगा नींव का पत्थर- राज्य पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल में जनपद संस्कृत सम्मेलन हुआ

भोपाल संस्कृत, भारत की प्राचीनतम भाषा है, संस्कृत के उत्थान से देश का उत्थान होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की वर्ष 2047 के विकसित भारत संकल्पना को साकार करने में संस्कृत भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका एवं योगदान होगा। संस्कृत के माध्यम से देश, पुनः भारतीय ज्ञान परम्परा से जुड़कर विश्व के समक्ष स्वत्व की पहचान पुनर्स्थापित करेगा। यह बात उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने भोपाल के वैशालीनगर स्थित राज्य पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान के सभागार में महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान एवं संस्कृत भारती मध्यभारत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित जनपद संस्कृत सम्मेलन के शुभारंभ अवसर पर कही।

उच्च शिक्षा मंत्री श्री परमार ने कहा कि सभ्य एवं संवेदनशील समाज निर्माण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसरण में शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं। अपनी भाषा के उत्थान के संकल्प, तथ्यों एवं सही इतिहास के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप क्रियान्वयन किया जा रहा है। अपनी भाषा, ज्ञान परम्परा, गौरवशाली इतिहास एवं अपनी उपलब्धियों पर गर्व के भाव के साथ लोकतांत्रिक और संवैधानिक रूप से, राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए सभी की सहभागिता आवश्यक है। श्री परमार ने कहा कि सैंकड़ों वर्षों के कठिन संघर्ष और दृढ़ संकल्प से श्री राम मंदिर की पुनर्स्थापना हुई है। भारत को विश्व मंच पर विश्वगुरु बनकर परम वैभव की प्राप्ति और देश में आदर्श राम राज्य स्थापित करने के संकल्प में सभी को नींव का पत्थर बनने की आवश्यकता है। श्री परमार ने सम्मेलन की सार्थकता और सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने सम्मेलन में आयोजित संस्कृतमय वास्तु प्रदर्शनी एवं विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, भोपाल के अध्यक्ष श्री भरत बैरागी ने वैश्विक परिदृश्य में संस्कृत भाषा की परिदिशा पर विचार करने को कहा। श्री बैरागी ने कहा कि संस्कृत हमारे जीवन का अंग है। संस्कृत से सामाजिक और समसामायिक समस्याओं का समाधान संभव है। इस अवसर पर क्षेत्र संगठन मंत्री संस्कृत भारती मध्यक्षेत्र श्री प्रमोद पंडित, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के निदेशक प्रो. रमाकांत पांडेय, करुणाधाम आश्रम भोपाल के पं. सुदेश शांडिल्य, संस्कृत भारती के प्रांताध्यक्ष एवं अपर संचालक पशुपालन विभाग सीहोर डॉ.अशोक भदौरिया सहित विभिन्न अधिकारी-पदाधिकारीगण एवं विद्यार्थी उपस्थित थे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008